

# वन गावों में सौर ऊर्जा से मोबाइल चार्जिंग

## भारत डोगरा

**आ**म धारणा यह है कि निर्धन वर्ग को सरकार कई प्रकार की सहायता देती है, मगर इस बारे में बहुत कम चर्चा है कि प्रायः धनी वर्ग को बहुत कम कीमत पर या निःशुल्क मिलने वाली सुविधाएं भी निर्धन वर्ग को महंगी उपलब्ध होती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले के आदिवासी, दलित व अन्य निर्धन परिवारों का अनुभव तो यही कहता है।

उन्होंने लोगों को मोबाइल फोन पर बातें करते देखा, तो किसी तरह बचत करके वे भी मोबाइल फोन खरीद लाए। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अपने बहुत दूर जंगल में बसे गांव में भी वे अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर लिया करेंगे। जब कोई मज़दूरी के लिए बाहर जाएगा, तो उसका कुशल-क्षेम पूछ लिया करेंगे। वे कभी-कभी पेड़ पर चढ़कर भी बात करते क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पर सिग्नल आसानी से मिल जाता है।

पर एक कठिनाई थी। इन गांवों में बिजली नहीं है। वे अपना फोन चार्ज नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें 7-10 कि.मी. दूर जाना पड़ता था। वहां एक बार फोन चार्ज करने के लिए 5-7 रुपए देना पड़ते थे। इससे कहीं अधिक क्षति उनकी मज़दूरी की होती थी क्योंकि आने-जाने में आधा दिन लग जाता था। फोन को चार्ज करना शहरों में बहुत सामान्य बात है वहीं इन दूर-दराज़ के गांवों के गरीब लोगों को इतना महंगा पड़ रहा था।

इन लोगों की इस समस्या का समाधान खोजा बुंदेलखंड सेवा संस्थान ने। यह संस्था इन परिवारों के अधिकारों के लिए व सरकार के विभिन्न कार्यक्रम उन तक पहुंचाने के लिए वर्षों से प्रयासरत रही है। अतः फोन चार्ज करने की समस्या के साथ इन घरों का अंधेरा दूर करने के लिए भी इस संस्था ने सोचना आरंभ किया।

शाम ढलने के साथ इन गांवों में अंधेरा छा जाता था। न बच्चे पढ़ पाते थे, न रात को कोई अन्य काम हो पाता था। बिच्छू के काटने का डर अलग बना रहता था। मिट्टी के तेल की जलती ढिबरी पलट जाने से एक बार आग लग गई तो एक महिला की बहुत दर्दनाक मौत हुई।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बुंदेलखंड सेवा संस्थान ने दिल्ली स्थित संस्थान 'दी एनर्जी रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट' (टेरी) से संपर्क किया। 'टेरी' सोलर पैनल व तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने को तैयार तो हो गई, पर प्रति गांव 40,000 रुपए खर्च बताया। दस गांव का खर्चा चार लाख रुपए बैठा जो इन निर्धन परिवारों की पहुंच से बाहर था। पर सेवा संस्थान ने प्रयास जारी रखे व स्थानीय व्यापारियों से चंदा एकत्र कर यह धनराशि चुका दी।

अब यहां सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाया गया जिससे गांववासी स्थानीय स्तर पर ही आसानी से अपना मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं। सोलर लालटेन की भी व्यवस्था हो गई है जिससे उनके घर रोशन हो रहे हैं। इस चार्जिंग स्टेशन व सोलर पैनल के रखरखाव के लिए एक बार चार्जिंग के लिए 2 रुपए सहयोग राशि ली जाती है।

मामूली से शुल्क को गांववासी सहर्ष दे देते हैं क्योंकि यह पहले के खर्च से कहीं कम है व इसके लिए उन्हें दूर भी नहीं जाना पड़ता है और एक दिन की मज़दूरी खोने का डर भी नहीं है। सोलर लालटेन की रोशनी से बच्चों की पढ़ाई व अन्य ज़रूरी कार्य हो जाते हैं। अब इन गांवों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के अधिक लाभ पहुंचाने की योजना बन रही है। ग्राम ऊर्जा समिति का गठन किया गया है जिसमें गांववासी अपनी ओर से भी थोड़ा बहुत चंदा देते हैं। (*स्रोत फीचर्स*)